डाक पंजीयन क्रमांक-म.प्र./भोपाल/357/2018-20

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

● वर्ष 61 ● अंक 24 ● भोपाल ● 16-31 मई, 2018 ● पृष्ठ 8 ● एक प्रति 7 रु. ● वार्षिक शुल्क 150/- ● आजीवन शुल्क 1500/-

आजीविका मिशन ने घर और समाज में महिलाओं का सम्मान बढ़ाया : श्री सारंग

15 जुलाई को जिला मुख्यालयों पर होंगे रोजगार मेले -श्री देशमुख

भोपाल। सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विश्वास सारंग ने कहा है कि राज्य आजीविका मिशन से घर और समाज में महिलाओं का सम्मान बढ़ा है, महिलाएँ आर्थिक और सामाजिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं। उन्होंने मिशन से जुड़ी 25 लाख से अधिक महिलाओं से प्रदेश सरकार के नशा मुक्ति अभियान से जुड़ने की अपील की। श्री सारंग यहाँ मध्यप्रदेश राज्य आजीविका मिशन द्वारा आजीविका एवं कौशल विकास दिवस पर अपेक्स बैंक के समन्वय भवन में आयोजित सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। राज्य कौशल एवं रोजगार बोर्ड के अध्यक्ष श्री हेमन्त विजय राव देशमुख ने समारोह की अध्यक्षता की।

राज्य मंत्री श्री सारंग ने कहा है कि भारतीय संस्कृति में महिला को शक्ति की प्रतिमूर्ति माना जाता है। जब महिलाएँ सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से सशक्त बनेंगी, तब ही परिवार, प्रदेश एवं राष्ट्र सशक्त बनेगा। उन्होंने महिलाओं से आजीविका के 12 सूत्रों के साथ 13वें सूत्र के रूप में संस्कार, संस्कृति और सभ्यता को सुदृढ़ बनाने का आव्हान किया। राज्य कौशल एवं रोजगार बोर्ड के अध्यक्ष श्री हेमन्त विजय राव देशमुख ने कहा कि आजीविका मिशन ने महिलाओं को घर की चार दिवारी से बाहर निकालकर आर्थिक स्वालम्बन प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि कौशल एवं रोजगार बोर्ड भी इस दिशा में लगातार प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में 15 जुलाई को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में रोजगार मेलों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है। कार्यक्रम के प्रारंभ में आजीविका मिशन के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एल.एम. बेलवाल ने बताया कि मध्यप्रदेश में स्व-सहायता समूह से 25 लाख महिलाओं को जोड़ा जा चुका है। इनमें से डेढ़ लाख से अधिक महिला सदस्यों की आय एक लाख रूपये से अधिक हो गई। एक लाख 58 हजार समूहों को बैंकों के माध्यम से 2024 करोड़ रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा चुकी है। सम्मेलन स्थल पर आजीविका समूहों के उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई। अपर मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैस ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और हितग्राहियों से चर्चा की।

किसानों को सहायता देने के लिये बना 1000 करोड़ का स्थिरीकरण कोष

भोपाल। प्रदेश में किसानों को सहायता प्रदान करने के लिये किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग द्वारा 1000 करोड़ रूपये की राशि से **मध्यप्रदेश मूल्य स्थिरीकरण कोष** बनाया गया है। इस कोष से किसानों को कृषि उत्पादन के बाजार मूल्य में गिरावट आने पर आर्थिक मदद पहुँचायी जा रही है।

प्रदेश में कृषि क्षेत्र की समस्याओं और न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में सिफारिश देने के लिये मध्यप्रदेश कृषि लागत और विपणन आयोग गठन किया गया है। यह आयोग वर्ष के तीन फसल मौसम के पूर्व अपनी रिपोर्ट देगा। आयोग में कृषि विशेषज्ञों, कृषि अर्थशास्त्रियों और प्रगतिशील किसानों को सदस्य बनाया गया है। यह आयोग मण्डी अधिनियम, कांट्रेक्ट फार्मिंग और उद्यानिकी फसलों के संबंध में भी राज्य सरकार को अनुशंसाएँ देगा।

श्री केदारलाल शर्मा, आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएँ

भोपाल। राज्य शासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की पदस्थापना की है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किये गये हैं। जारी आदेशानुसार श्री केदारलाल शर्मा, सचिव गृह विभाग को आयुक्त–सह– पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ तथा प्रबंध संचालक, राज्य सहकारी तिलहन उत्पादक संघ (अतिरिक्त प्रभार) और श्रीमती स्वाति मीणा नायक, संचालक नगर तथा ग्राम निवेश को प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ, भोपाल पदस्थ किया गया है।

किसानों के खातों में पहुंचे 3527 करोड़

भोपाल। मध्यप्रदेश में किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के प्रयासों के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा पिछले छह माह में किसानों के खातों में लगभग 3527 करोड़ की राशि विभिन्न योजनाओं के जरिये जमा करवाई गई है। इन योजनाओं में किसानों का ऐतिहासिक कवच के रूप में जानी गई मुख्यमंत्री किसान भावान्तर योजना और मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना प्रमुख हैं। इसके अलावा रबी 2017-18 में चना, मसूर, सरसों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिये पंजीकृत लगभग 15 लाख किसानों के खातों में 100 रुपये प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि के रूप में इस वर्ष 15 हजार करोड़ रुपये पहुँचाये जायेंगे। उल्लेखनीय है कि पंजीकृत किसानों से 10 अप्रैल से 9 जून की अवधि में 21 लाख मी.टन चना, 3 लाख मी.टन मसूर और 4 लाख मी.टन सरसों की समर्थन मूल्य पर खरीदी की व्यवस्थाएँ की गई हैं।

अभी तक किसानों के खाते में पहुँचाई गई 3527 करोड़ की राशि में 1677 करोड़ की राशि रबी 2016-17 की धान की खरीदी पर 200 रुपये प्रति क्विंटल के मान में दी गई प्रोत्साहन राशि शामिल है। वर्ष 2017-18 के लिये पायलट आधार पर लागू की गई भावांतर भुगतान योजना के अंतर्गत 12 लाख किसानों के खाते में जमा की गई 1850 करोड़ की भावांतर राशि भी इसी में शामिल है।

राज्य सरकार ने रबी मार्केटिंग सीजन 2018-19 में ई-उपार्जन में गेहूँ बेचने वाले किसानों को प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया है। इस वर्ष 26 मई तक मण्डी में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूँ बेचने वाले किसानों को मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना में 265 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर प्रोत्साहन राशि दी जायेगी। इसी सीजन में ई-उपार्जन का पंजीयन करवाने वाले किसानों, जो चना, मसूर और सरसों का विक्रय करेंगे, को 9 जून की अवधि में विक्रय करने पर 100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से प्रोत्साहन राशि दी जायेगी।

पैक्स फसल ऋण भुगतान तिथि में वृद्धि

भोपाल। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स) द्वारा खरीफ 2017 में वितरित अल्पकालीन फसल ऋण भुगतान की तिथि 25 मई तक बढ़ा दी गई है। पूर्व में यह तिथि 27 अप्रैल 2018 निश्चित की गई थी। प्रमुख सचिव सहकारिता ने इस आशय के आदेश जारी कर दिये हैं।

मुख्यमंत्री द्वारा अलीराजपुर जिला खुले में शौच से मुक्त घोषित

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अलीराजपुर ने खुले में शौच मुक्ति के अभियान में प्रशंसनीय कार्य किया है। इस सम्मान को बनाये रखने का प्रयास जारी रखे। श्री चौहान अलीराजपुर में खुले में शौच से मुक्ति के उत्सव एवं असंगठित श्रमिक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नर्मदा उद्वहन सिंचाई योजना से वर्ष 2020 सें क्षेत्र में भरपूर सिंचाई हो सकेगी।

श्री चौहान ने 52 करोड़ 53 लाख 86 हजार रुपये लागत के 20 विभिन्न निर्माण कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने खुले में शौच मुक्ति के लिये जिले के प्रयासों की पुस्तक का विमोचन भी किया। श्री चौहान ने जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती अनीता चौहान को खुले में शौच से मुक्ति का प्रमाण-पत्र भी प्रदान किया। साथ ही ओडीएफ कार्य में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों सहित मैदानी स्टॉफ को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को हित-लाभ-पत्र भी बाँटे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान का पारम्परिक आदिवासी झुलड़ी और तीर-कमान भेंट कर स्वागत किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आजीविका मिशन के माध्यम से गठित समूहों को मिलने वाले बैंक ऋण राशि की 3 प्रतिशत ब्याज राशि राज्य सरकार देगी। उन्होंने कहा कि होशंगाबाद जिले की महिलाओं द्वारा शुरू किया गया। मुर्गी-पालन और मुर्गी दाना कारखाना जैसा प्रयास अलीराजपुर में भी हों। मुख्यमंत्री ने कहा कि सौभाग्य योजना का लाभ भी जिले के सभी लोगों को पहुँचाया जाये।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने असंगठित मजदूरों के पंजीकृत व्यक्तियों की सूची का ग्रामसभा में वाचन के लिये उचित प्रबंध करने को कहा। उन्होंने कहा कि महुआ फूल बीनने वालों को चप्पल-जूते और पानी की कुप्पी भी अब उपलब्ध करवाई जा रही है।

मुख्यमंत्री ने समारोह में नागरिकों को बच्चों को अनिवार्य रूप से स्कूल भेजने, ग्रामों को स्वच्छ रखने, पानी रोकने और पौध-रोपण करने का संकल्प दिलवाया।

विधायक श्री नागर सिंह चौहान ने भी समारोह को संबोधित किया। यूनीसेफ की सुश्री मारिया ने कहा कि खुले में शौच मुक्ति के अभियान में अलीराजपुर जिले में सराहनीय काम हुआ है। व्यवहार परिवर्तन कर बड़े बदलाव में समुदाय ने बड़ा प्रयास किया है। श्रम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री बालकृष्ण पाटीदार और असंगठित शहरी एवं ग्रामीण कर्मकार कल्याण मण्डल अध्यक्ष श्री सुल्तान सिंह शेखावत भी उपस्थित थे।

कृषि से आमदनी बढ़ाने के लिये किसानों ने अपनाई आधुनिक तकनीक

भोपाल। प्रदेश में किसान अब अपनी आय बढ़ाने के लिये कृषि विशेषज्ञों की मदद से नई-नई तकनीक अपना रहे हैं। इससे किसानों के जीवन-स्तर में काफी बदलाव आया है।

पन्ना जिले के ग्राम अहिरगुवा के किसान अग्निमित्र शुक्ला के पास तीन हेक्टेयर सिंचित रकबा हैं। इस वर्ष अग्निमित्र को दो एकड़ में चने का लगभग दो गुना उत्पादन मिला है। उन्होंने बताया कि पूर्व वर्षों की तुलना में 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के स्थान पर 34 क्विंटल प्रति हेक्टेयर चने का उत्पादन प्राप्त हुआ है। किसान अग्निमित्र बताते हैं कि वे पिछले 7-8 वर्षों से चने की खेती कर रहे हैं। उन्होंने अपने खेत में विभिन्न किस्मों के चने की बोनी की। इन सबके बावजूद उन्हें कभी भी 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से अधिक चने का उत्पादन प्राप्त नहीं हुआ। इस संबंध में उन्होंने वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी से चर्चा की। कृषि विभाग की चना क्लस्टर प्रदर्शन योजना के अंतर्गत अग्निमित्र को चने का जे.जी.-63 प्रजाति का 60 किलो बीज दिया गया। उन्होंने इस बीज को दो एकड़ में बोया, कृषि अधिकारियों की सलाह पर खेत में मृदा स्वास्थ्य कार्ड की अनुशंसा पर उर्वरक भी डाला। इससे बीज का अंकुरण और पौधों की बढ़त भी अच्छी हुई। कृषि की इस तकनीक को अपनाने से इन्हें 34 क्विंटल प्रति हेक्टेयर चने का उत्पादन प्राप्त हुआ है। आज वे इस तकनीक को अपने किसान साथियों को बताते हैं तो वे आश्चर्यचकित रह जाते हैं। अब क्षेत्र के अन्य किसानों ने भी चने की जे.जी.-63 प्रजाति को अपनाने का मन बना लिया है।

खरगोन जिले की कसरावद तहसील के किसान महेंद्र पाटीदार ने उद्यानिकी विभाग के सहयोग से नींबू का बगीचा तो लगा लिया, लेकिन पानी की समस्या ने उनकी चिंता बढ़ा दी थी। ऐसे समय में नव-विवाहित महेंद्र ने अपनी पत्नि को साथ लेकर, बैलगाड़ी पर कोठी बाँधकर एक-एक पौधे को कढ़ी धूप में पानी देकर सिंचाई की पाँच वर्षो के बाद नींबू को पहली फसल आई। पहली फसल से कोई खास मुनाफा तो नहीं हुआ, मगर अंतरवर्ती फसलों कपास, गेहूँ और सोयाबीन के सहारे उनको मुनाफा होता रहा। इसके लगातार बाद 5 वर्षो से उन्हें मुनाफा ही मिल रहा है। अब अग्निमित्र क्षेत्र के प्रतिशील किसान की श्रेणी में भी शामिल हो गये है।

उद्यानिकी विभाग से किसान

महेंद्र को एक हेक्टेयर में मल्चिंग शीट के लिए 10 हजार रुपए की सब्सिडी भी मिली। इसके बाद महेंद्र ने मल्चिंग विधि से तरबूज की खेती की और एक लाख 29 हजार 600 रुपए खर्च कर 5 लाख 70 हजार 567 रुपए का शुद्ध मुनाफा लिया। महेंद्र ने मात्र 80 दिनों की तरबूज की फसल में 75 हजार 960 किलोग्राम तरबूज की फसल ली। कृषि और उद्यानिकी विभाग के जानकार बताते हैं कि निमाड़ में मल्चिंग विधि से तरबूज की फसल सफलतापूर्वक लेने वाले महेंद्र पहले किसान हैं। अब महेंद्र कृषि की नई-नई तकनीकों को अपनाकर अलग-अलग प्रयोग करने में जुट गए हैं।

म.प्र. में एक लाख 57 हजार महिलाओं को नि:शुल्क मिले ड्रायविंग लायसेंस

भोपाल। प्रदेश में महिलाओं को नि:शुल्क ड्रायविंग लायसेंस देने की योजना में अभी तक एक लाख 57 हजार 470 ड्रायविंग लायसेंस जारी किये गये हैं। इनमें से एक लाख 38 हजार लायसेंस महिलाओं के लिये लगाये गये विशेष पिंक लायसेंस शिविरों में बने और वितरित हुए हैं। यह योजना 28 दिसम्बर 2015 से लागू की गई है। इसमें अभी तक 2 लाख 27 हजार 604 लर्निंग ड्रायविंग लायसेंस भी बनाये गये हैं।

मध्यप्रदेश में हर आदिवासी को दिया जायेगा पक्का मकान : श्री चौहान

ग्राम सुतरेटी में मुख्यमंत्री ने हितग्राहियों को दिया हित-लाभ

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने झाबुआ जिले के ग्राम सुतरेटी में असंगठित श्रमिक एवं तेंदूपत्ता संग्राहक सम्मेलन में कहा कि प्रदेश में फसल काटने, गिट्टी तोड़ने और हम्माली करने वाले श्रमिकों तथा ढ़ाई एकड़ से कम जमीन वाले किसानों को विभिन्न योजनाओं का भरपूर लाभ दिया जायेगा। राज्य सरकार बिना किसी भेदभाव के सभी जरूरतमंदों और गरीबों को जन-कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित कर रही है। श्री चौहान ने इस मौके पर नर्मदा-झाबुआ सिंचाई परियोजना के लिये 2050.70 करोड़ रूपये स्वीकृत करने की घोषणा की। सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के पात्र हितग्राहियों को हित-लाभ एवं वनाधिकार पट्टों का वितरण किया।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि झाबुआ जिले में असंगठित श्रमिक कल्याण योजना में पंजीकृत 3 लाख 66 हजार गरीबों को जमीन का मालिक बनाया जाएगा। प्रत्येक पट्टे पर प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनवाकर दिए जायेंगे। वर्ष 2022 तक सभी आदिवासियों को पक्के मकान बनवाकर दिये जायेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गरीबों को मकान के लिए जमीन और बिजली प्राथमिकता के आधार पर दी जाएगी। श्री चौहान ने कहा कि राज्य सरकार पंडित दीनदयाल के आदर्शों पर चलकर गरीबों के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। प्रदेश में विगत एक अप्रैल से पंजीकृत श्रमिकों को 200 रुपये प्रति माह की दर से घरेलू बिजली दी जा रही है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि भारत सरकार की आयुष्मान योजना का लाभ मध्यप्रदेश की जनता को भी दिलवाया जाएगा। साथ ही, गरीब बहनों को सम्मानजनक व्यवसाय के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं की विस्तार से जानकारी देते हुए नागरिकों से अपील की विशेष ग्राम सभा में अवश्य भाग लें। सभा में असंगठित मजदूरों के पंजीयन की सूची पढ़ी जायेगी। उन्होंने श्रमिकों से आग्रह किया कि अगर सूची में नाम छूट गया हो, तो विशेष ग्राम सभा में ही अपना नाम जुड़वाएँ।

सम्मेलन में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने श्रमिकों, तेंदूपत्ता संग्राहकों एवं महुआ फूल बीनने वाले श्रमिकों को चरण पादुका, साड़ी और पानी की बॉटल का वितरण किया। विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को हित-लाभ भी वितरित किये। मुख्यमंत्री ने आदिवासी बोली की नुक्कड़ नाटक पुस्तिका **पोरियों नी हन्देहो** का विमोचन किया और नागरिकों को बच्चों को पढ़ाने, जल-संरक्षण, गाँव को सुंदर और स्वच्छ बनाने, घर में शौचालय बनाने, पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाने और वृक्ष बचाने का संकल्प दिलवाया। कार्यक्रम में विधायक श्री कलसिंह भाबर और श्री शांतिलाल बिलवाल तथा राज्य लघु वनोपज संघ के अध्यक्ष श्री महेश कोरी उपस्थित थे।

एम.एस.पी. पर अब तक करीब 48 लाख 72 हजार मीट्रिक टन गेहूँ की खरीदी

भोपाल। प्रदेश में किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूँ की खरीदी की जा रही है। अब तक 2897 उपार्जन केन्द्रों से 6 लाख 26 हजार 289 किसानों से 48 लाख 71 हजार 882 मीट्रिक टन गेहूँ की खरीदी की जा चुकी है। समर्थन मूल्य 1735 रुपये प्रति क्विंटल और 265 प्रति क्विंटल बोनस किसानों को देय होगा। इस प्रकार किसान को समर्थन मूल्य पर गेहूँ विक्रय करने पर प्रति क्विंटल 2000 रुपये का भुगतान होगा। खरीदी के लिये कुल 3016 केन्द्र बनाये गये हैं।

गेहूँ उपार्जन 25 मई तक जारी रहेगा। इंदौर और उज्जैन संभाग के जिलों में 15 मई, भोपाल और नर्मदापुरम संभाग के जिलों में 20 मई और अन्य संभाग के जिलों में 25 मई तक उपार्जन किया जायेगा।

उपार्जन केन्द्रों से प्राप्त जानकारी

खरीदी 25 मई तक जारी रहेगी

में सर्वाधिक खरीदी भोपाल संभाग के जिलों के 559 उपार्जन केन्द्रों पर हुई है। अब तक भोपाल संभाग में एक लाख 54 हजार 419 किसानों से 12 लाख 74 हजार 266 मीट्रिक टन गेहूँ खरीदा गया है।

नर्मदापुरम संभाग के जिलों के 290 उपार्जन केन्द्रों पर 90 हजार 316 किसानों से 10 लाख 26 हजार 16 मीट्रिक टन गेहूँ, उपार्जित किया गया है। इंदौर संभाग के जिलों के 334 उपार्जन केन्द्रों पर 72 हजार 381 किसानों द्वारा अब तक 4 लाख 74 हजार 773 मीट्रिक टन गेहूँ समर्थन मूल्य पर बिक्री किया गया है। उज्जैन संभाग के 287 उपार्जन केन्द्र पर 1 लाख 10 हजार 197 किसानों ने 6 लाख 91 हजार 114 मीट्रिक टन गेहूँ विक्रय किया। ग्वालियर संभाग के जिलों के 251 उपार्जन केन्द्र पर अब तक 33 हजार 669 किसानों ने 2 लाख 97 हजार 387 मीट्रिक टन गेहूँ का विक्रय किया है। चम्बल संभाग के जिलों के 114 उपार्जन केन्द्रों पर खरीदी जारी है। अब तक इन केन्द्रों पर 17 हजार 676 किसानों द्वारा एक लाख 57 हजार 437 मीट्रिक टन गेहूँ विक्रय किया गया है। सागर संभाग के गेहूँ उपार्जन के जिलों के 375 उपार्जन केन्द्रों पर 3 लाख 73 हजार 897 मीट्रिक टन गेहूँ का उपार्जन हुआ है। सागर संभाग के जिलों के 73 हजार 201 किसान इससे अब तक लाभान्वित हुए हैं। जबलपुर संभाग के जिलों के 54 हजार 33 किसानों ने 4 लाख 52 हजार 975 मीट्रिक टन गेहूँ उपार्जन केन्द्रों पर बिक्री किया है। रीवा संभाग के जिलों के 211 केन्द्रों पर 19 हजार 701 किसानों ने एक लाख 21 हजार 545 मीट्रिक टन गेहूँ को अब तक समर्थन मूल्य पर विक्रय किया गया है। शहडोल संभाग के जिलों के कुल 44 केन्द्रों पर अब तक 696 किसानों द्वारा 2468 मीट्रिक टन गेहूँ को समर्थन मूल्य पर विक्रय किया गया है।

चना, मसूर, सरसों की भी समर्थन मूल्य पर खरीदी जारी

राज्य सरकार द्वारा किसानों से चना, मसूर और सरसों का भी समर्थन मूल्य पर उपार्जन किया जा रहा है। इसके लिये बनाये गये 586 उपार्जन केन्द्र में से 563 पर खरीदी की जा रही है। इन 563 उपार्जन केन्द्रों पर एक लाख 18 हजार 760 किसानों द्वारा एक लाख 77 हजार 748.93 मीट्रिक टन चना, सरसों और मसूर की खरीदी अब तक की गई है। खरीदी की इस यात्रा में एक लाख 905 किसानों में से एक लाख 49 हजार 122.65 मीट्रिक टन चना की खरीदी, 21 हजार 347 किसानों से 19 हजार 916.45 मीट्रिक टन मसूर और 7399 किसानों से 10 हजार 160 मीट्रिक टन सरसों की खरीदी शामिल है।

प्रमुख सचिव श्री राजन ने किया सीहोर में खरीदी केन्द्रों का निरीक्षण

भोपाल। प्रमुख सचिव पर्यावरण श्री अनुपम राजन ने सीहोर में गेहूँ, चना, मसूर एवं सरसों की खरीदी की समीक्षा की। श्री राजन ने गेहूँ उपार्जन केन्द्र पिपलिया मीरा, बिल्कीसगंज, सायलो सेन्टर सीहोर एवं कृषि उपज मंडी में उपार्जन केन्द्रों का निरीक्षण कर कृषकों से चर्चा की। कृषकों ने बताया कि गेहूँ विक्रय की राशि 3 से 7 दिनों में बैंक खाते में आ जाती है। साथ ही कृषकों ने पिछले वर्ष विक्रय किये गये गेहूँ की 200 रुपये प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि प्राप्त होने पर हर्ष व्यक्त किया। प्रमुख सचिव के निरीक्षण के दौरान उपार्जन कार्य से जुड़े विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित थे।

जन सहोयग से जल संरक्षण और संवर्धन का महाभियान चलेगा : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने कोलांस नदी में श्रमदान कर महाअभियान की शुरूआत की

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भू-जल स्तर निरंतर गिर रहा है। इसे रोकने के लिये प्रदेश में जन-सहयोग से जल-संरक्षण और संवर्धन का महाभियान चलाया जायेगा। पुराने तालाबों और नदियों का गहरीकरण किया जायेगा। साथ ही इस वर्ष 500 करोड़ रूपये से नये तालाबों का निर्माण किया जायेगा। इस वर्ष 15 जुलाई से वृक्षारोपण का अभियान भी शुरू होगा। श्री चौहान ने इस महती कार्य में शामिल होने के लिये संपूर्ण समाज का आव्हान किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज सीहोर जिले के ईंटखेड़ी छाप में आयोजित जल-संसद को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कोलांस नदी के गहरीकरण के लिये श्रमदान का शुभारंभ भी किया। उन्होंने स्वयं श्रमदान कर लोगों को श्रमदान के लिये प्रेरित भी किया।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मनुष्य द्वारा औद्योगिकीकरण और भौतिकता की चाह में प्राकृतिक संसाधनों का अँधाधुँध दोहन किया गया है। इससे अनेक प्राकृतिक आपदाएँ उत्पन्न हुई हैं। वृक्षों की अँधाधुँध कटाई से वर्षा कम और अनियमित होने लगी है। आज पर्यावरण बिगड़ रहा है, नदियाँ सूख रही हैं और सतही जल लगातार घट रहा है। धरती पर सूखे का संकट पैदा हो रहा है। धरती की सतह का तापमान लगातार बढ़ रहा है, जो वर्ष 2050 तक दो डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जायेगा। इससे ग्लेशियर पिघलेंगे, समुद्र का जल-स्तर बढ़ेगा और बाढ़ जैसी समस्याएँ पैदा होंगी।

श्री चौहान ने कहा कि इन समस्याओं का पूरी दुनिया और देश सामना कर रहा है। ये समस्याएँ क्यों पैदा हुईं, यह सभी के लिये चिंता और सोचने का विषय है। अगर हम अभी नहीं चेते तो आने वाली पीढ़ियों के लिये भारी संकट पैदा होगा। यह धरती मनुष्यों के साथ पेड़-पौधों और जीव-जंतुओं के लिये भी है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों का शोषण नहीं दोहन करना चाहिए। वृक्ष वर्षा जल को अवशोषित करते हैं जिससे भू-जल स्तर बढ़ता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नदियाँ जीवन का आधार हैं। मानव सभ्यता नदियों के किनारे ही विकसित हुई हैं। पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों को बचाना हमारा लक्ष्य है। आगामी 15 जुलाई से 30 अगस्त तक महावृक्षारोपण अभियान शुरू होगा। उन्होंने कहा कि वर्षा जल को रोकने के लिये चेक डेम, बोरी बँधान और तालाब निर्माण का कार्य किया जायेगा। उन्होंने कहा कि गाँव का पानी गाँव में ही रोकने के उपाय किये जायेंगे। इसमें स्वयंसेवी संस्थाएँ एवं सभी लोग सहयोग करें। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जब भी कोई बड़ा कार्य शुरू करते हैं तो उसमें रूकावटें आती ही हैं। लोग क्या कहेंगे, इसकी चिंता नहीं करें। यह कार्य केवल सरकार नहीं कर सकती, संपूर्ण समाज के सहयोग से ही संभव है। उन्होंने इस पुण्य कार्य में शामिल होने के लिये सभी से अपील की। मुख्यमंत्री ने जल-संरक्षण के लिये जन-अभियान परिषद द्वारा सभी 313 विकासखण्डों में नदियों के गहरीकरण के लिये शुरू किये गये श्रमदान की प्रशंसा की।

श्री चौहान ने बताया कि विगत वर्ष की गई नर्मदा सेवा यात्रा से लोगों में नदियों के प्रति जागरूकता बढ़ी है। अब लोग नदियों में दूषित जल-प्रवाह करने से परहेज करते हैं। नदी के किनारे विसर्जन-कुण्ड, पूजन-कुण्ड, शौचालय और मुक्ति-धाम बनाये गये हैं। साथ ही तट के गाँव से शराब की दुकानें हटाई गई हैं। नर्मदा नदी के किनारे विगत दो जुलाई को 35 लाख लोगों द्वारा 6 करोड़ से अधिक पौधे रोपे गये थे। उन्होंने लोगों को पर्यावरण और नदी संरक्षण का संकल्प भी दिलाया। साथ ही स्वयं भी चिलचिलाती धूप में गैती लेकर कोलांस नदी में श्रमदान किया।

जन-अभियान परिषद के उपाध्यक्ष डॉ. प्रदीप पाण्डे ने बताया कि आज से नदी गहरीकरण के जन-अभियान की शुरूआत हो रही है। जो आगामी दो माह तक प्रदेश के 313 विकासखण्डों में चलेगा। गौ-संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष स्वामी श्री अखिलेश्वरानंद ने कहा कि भारतीय संस्कृति बहुत उदार है। इसमें सभी जीव-जंतुओं, जड़-चेतन को भी चैतन्य माना गया है। भारत एक जीवंत चेतना है। इसमें प्रकृति को पूरा सम्मान दिया गया है। बिना जल के जीवन संभव नहीं है। इसलिये जड़-जंतु, जल को सुरक्षित रखें। विधायक श्री रामेश्वर शर्मा ने कहा कि कोलांस नदी से भोपाल का बड़ा तालाब भरता है। उन्होंने नदी गहरीकरण के कार्य के लिये परिषद की सराहना की। मुख्यमंत्री ने परिषद द्वारा आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया।

इस मौके पर सांसद श्री आलोक संजर, भोपाल महापौर श्री आलोक शर्मा, मध्यप्रदेश खनिज विकास निगम के अध्यक्ष श्री शिव चौबे, जन-अभियान परिषद के उपाध्यक्ष श्री राघवेन्द्र गौतम, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री मनमोहन नागर आदि जन-प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में आमजन मौजूद थे।

आजीविका मिशन के एक लाख 34 हजार सदस्य बने रखपति

स्व-सहायता समूहों को आर्थिक गतिविधियों के लिए दिए गये 2024 करोड़ रुपये

भोपाल। ग्रामीण निर्धन परिवारों की महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्म-निर्भर बनाने के लिए संचालित मध्यप्रदेश राज्य आजीविका मिशन से स्व-सहायता समूहों के एक लाख 34 हजार सदस्य लखपति बन गये है। हर सदस्य की आय अब एक लाख रुपये से अधिक हो गई है। इस अभियान में 2 लाख 8 हजार स्व-सहायता समूहों में 23 लाख 88 हजार परिवार अपना जीवकोपार्जन कर रहे हैं। इनमें से एक लाख 58 हजार 393 समूहों को ऋण के रूप में बैंको से 2024 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई गई है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी आजीविका मिशन ग्रामीण श्री वेलबाल ने बताया कि प्रदेश के 43 जिलों के 271 विकासखंडों में मिशन की गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं, जिसमें 6 लाख 55 हजार ग्रामीण बेरोजगार युवकों को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण उपलब्ध करवाया गया है।

स्व-सहायता समूह में आर्थिक गतिविधियों का लेखाजोखा ठीक तरह से संधारित करने के लिए एक लाख 8 हजार 187 समूहों को बुक कीपिंग का प्रशिक्षण दिलवाया गया है। स्व-सहायता समूहों द्वारा विभिन्न रोजगार मूलक गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। प्रदेश में 498 समूहों द्वारा उत्पादित सब्जियों के विक्रय के लिए आजीविका फ्रेश संचालित किए जा रहे हैं और 14 हजार 670 समूहों द्वारा वस्त्र निर्माण की गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं। इसी प्रकार 402 समूहों द्वारा सेनटरी नेपकिन निर्माण इकाई स्थापित की गई हैं, 528 समूहों द्वारा अगरबत्ती उत्पादन कार्य तथा 89 हजार 269 परिवारों द्वारा दुग्ध उत्पादन कार्य किया जा रहा है। डेढ़ लाख परिवार गैर कृषि आजीविका गतिविधियों में संलग्न हैं, 25 जिलों में 2877 समूहों द्वारा साबुन निर्माण, 698 समूहों द्वारा गुड़, मूंगफली, चिक्की निर्माण, 1236 समूहों द्वारा हाथकरघा उद्योग संचालित किये जा रहे हैं। प्रदेश में 37 समूह बड़ी औद्योगिक इकाईयों के सहयोगी उत्पाद बना रहे हैं।

जरबेरा फूलों की खेती से 30 लाख सालाना कमा रहे कृषक शरद सिंह

भोपाल। एक एकड़ से कम रकबे में जरबेरा फूल उत्पादन से छिन्दवाड़ा जिले के किसान शरद सिंह सालाना 30 लाख रुपये की आय अर्जित कर रहे हैं। कृषक शरद सिंह ने 4 हजार वर्ग मीटर में 3 साल पहले 58 लाख रुपये की लागत से पॉली-हाऊस बनाया। पॉली-हाऊस में जरबेरा फूलों के उत्पादन से लगातार 30 लाख रुपये सालाना से %यादा की कमाई कर कृषक शरद ने इतिहास रचा है।

कृषक शरद को पॉली-हाऊस बनाने के लिये 50 प्रतिशत शासकीय अनुदान के रूप में 28 लाख रुपये की मदद मिली थी। इसे पॉली-हाऊस से सालाना 7-8 लाख जरबेरा फूलों की स्टिक प्राप्त होती है। यह स्टिक 5 रुपये प्रति स्टिक के भाव से कुल 35 से 40 लाख रुपये में बाजार में बिकती है। तमाम खर्चे निकालकर उन्हें शुद्ध रूप से 30 लाख रुपये से अधिक की सालाना आय होती है।

कृषक शरद सिंह ने साबित कर दिया है कि फूलों की व्यावसायिक खेती को नई तकनीक से किया जाये, तो यह बहुत फायदेमंद व्यवसाय है। मार्केट में फूलों की बिक्री की कोई समस्या नहीं है। शरद के जरबेरा फूल नागपुर की मंडी में बिकते हैं। इन फूलों की सुन्दरता और बड़े आकार के कारण मार्केट में इनकी माँग दिनों-दिन बढ़ती जा रही है।

गेहूँ उपार्जन 71 लाख मीट्रिक टन तक जाने की उम्मीद

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने की रबी उपार्जन की समीक्षा

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में गेहूँ, चना, सरसों और मसूर के उपार्जन की स्थिति की मंत्रालय में हुई उच्च-स्तरीय बैठक में विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने कहा कि परिवहन व्यवस्था के कारण उपार्जन प्रभावित नहीं होना चाहिए। श्री चौहान ने चने की खरीदी 30 मई से पहले पूरी करने के निर्देश दिए। गेहूँ उपार्जन की स्थिति पर संतोष व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने बिना किसी शिकायत के गेहूँ उपार्जन की पुख्ता व्यवस्था के लिए विभागीय और मैदानी अधिकारियों की सराहना की।

बैठक में बताया गया कि अब तक 61 लाख मीट्रिक टन गेहूँ की खरीदी हो गई है। अगले कुछ दिनों में यह खरीदी करीब 71 लाख मीट्रिक टन तक पहुँच जाएगी। गेहूँ उपार्जन के लिए 3000 से ज्यादा उपार्जन केंद्र संचालित हैं। अब तक चने की 4 लाख 36 हजार 333 मीट्रिक टन, सरसों की 31 हजार 310 मीट्रिक और मसूर की करीब 52 हजार मीट्रिक टन से ज्यादा की खरीदी हुई है।

बैठक में मुख्य सचिव बी.पी.सिंह, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री पी.सी.मीना, अपर मुख्य सचिव वित्त श्री ए.पी.श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव खाद्य श्रीमती नीलम शमी राव एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

कमरे बराबर पिंजरे में हो रहा है चार से पांच टन मछली का उत्पादन

केज कल्चर में मध्यप्रदेश अग्रणी राज्यों में

भोपाल। मत्स्य विभाग द्वारा कम पानी और कम जगह में अधिक मछली उत्पादन के लिये प्रदेश में केज कल्चर को प्रोत्साहित किया जा रहा है। विभाग द्वारा नई तकनीक का इस्तेमाल करते हुए प्रदेश में 6X4X4 मीटर के 580 केज में सफलता से मछली पालन कराया जा रहा है। प्रत्येक केज में औसत 96 घनमीटर जल क्षेत्र मिलता है। एक केज में 4 से 5 टन पंगेशियस मछली का उत्पादन हो रहा है। वैसे एक हेक्टेयर जल क्षेत्र में 2 टन मछली का उत्पादन प्राप्त होता है। पंगेशियस मछली थोक भाव में 80 रूपये प्रति किलो की दर से बिकती है।

केन्द्रीय नील क्रान्ति योजना और आदिवासी विशेष केन्द्रीय सहायता योजना में पिंजरों की स्थापना कर पंगेशियस मछली का उत्पादन किया जा रहा है। हर केज में 5 से 6 हजार पंगेशियस मत्स्य-बीज का संचयन किया जाता है। कम जल क्षेत्र में अधिक उत्पादन मिलने से यह तकनीक तेजी से लोकप्रिय हो रही है।

केज कल्चर में मध्यप्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। केज की स्थापना उन जलाशयों में की जाती है, जहाँ गर्मी के मौसम में भी जल की अधिकतम गहराई 7 मीटर तक होती है। केज का निर्माण एचडीपीई के मॉड्यूलर फ्लोटिंग डाक से होता है। केज जलाशय में तैरते रहते हैं। इनमें पाली जाने वाली पंगेशियस मछली को फ्लोटिंग फिश फीड दिया जाता है। मछली के खाने में यह ध्यान रखा जाता है कि उसमें प्रोटीन की मात्रा 28 से 30 प्रतिशत तक हो।

सहकारी प्रशिक्षण समितियों की कार्यप्रणाली को विकसित करने का सशक्त माध्यम

डाक तार सहकारी समिति में सहकारी प्रशिक्षण सम्पन्न

जबलपुर। सहकारी प्रशिक्षण सहकारी समितियों के सदस्यों की कार्यप्रणाली को विकसित करने और समितियों के विकास में सहायक सिद्ध होता है। ये विचार सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र जबलपुर द्वारा डाक कर्मचारी सहकारी समिति में आयोजित कार्यक्रम में प्रवर अधीक्षक श्री सूर्यकांत द्विवेदी ने मुख्य अतिथि के रूप में व्यक्त किये। उन्होंने समिति के अध्यक्ष श्री सुभाष जायसवाल की सेवा निवृत्ति के अवसर पर हार्दिक शुभकामनायें भी व्यक्त की और कहा कि किसी भी पदाधिकारी की सेवा निवृत्ति के पश्चात अन्य सदस्यों का दायित्व और बढ़ जाता है। और इसके लिये सदस्यों को समिति के संबंध में व्यापक जानकारी का होना आवश्यक है।

सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र के प्राचार्य श्री यशोवर्धन पाठक ने संबोधित करते हुए सदस्यों को अध्यक्ष संचालकों के कर्त्तव्य व दायित्व के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की और कहा कि अध्यक्ष सहित संचालकों के कर्त्तवय व दायित्व के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की और कहा कि अध्यक्ष नेतृत्व का प्रतीक होता है और नेतृत्व और प्रबंधन में समन्वय होना आवश्यक है। केन्द्र के प्रशिक्षक श्री रितेष कुमार ने सदस्यों को लेखाविधि एवं सहकारी विधान की उपयोगी जानकारी दी।

कार्यक्रम के दौरान सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र जबलपुर की ओर से अध्यक्ष श्री सुभाष जायसवाल को सम्मानित किया गया। अन्त में श्री सुभाष जायसवाल ने अपने अध्यक्षीय कार्यकाल के अनुभव सदस्यों के साथ साझा किये। कार्यक्रम का संचालन श्री संतोष नेमा संतोष ने किया।

लू से बरतें सावधानी

भोपाल। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री रुस्तम सिंह ने बढ़ते तापमान के मद्देनजर प्रदेशवासियों से आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है। श्री सिंह ने कहा कि लू के दुष्प्रभाव को गंभीरता से लेते हुए खुद को और अपने परिवार को बचाने के लिये ऐहतियाती उपाय अपनायें। बुखार आने पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रखें। नजदीकी शासकीय स्वास्थ्य केन्द्र में सम्पर्क करें।

भोजन-पानी करके ही घर से निकले

श्री सिंह ने कहा कि जब भी घर से बाहर निकलें भरपेट भोजन और पानी पीकर ही निकलें। धूप में खाली पेट बिल्कुल नहीं निकलें। अधिक से अधिक तरल पदार्थों का सेवन करें। छाछ, ओआरएस का घोल, लस्सी, नींबू पानी, आम पना आदि का सेवन करें। मिर्च-मसालेयुक्त बासी भोजन न करें।

कूलर या एयर-कण्डीशनर से एकदम धूप में न निकलें

सूती, ढीले एवं आरामदायक कपड़े पहनें, धूप में निकलते समय सिर ढंककर रखें। टोपी, कपड़ा, छतरी आदि का उपयोग भी करें।

लू के लक्षण

सिर दर्द, बुखार, उल्टी, अत्यधिक पसीना एवं बेहोशी, कमजोरी, शरीर में ऐंठन और असामान्य नब्ज। ऐसा होने पर व्यक्ति को छायादार जगह पर लिटायें। मरीज के कपड़े ढीले कर दें। उसे कच्चे आम का पना, प्याज का रस, पेय पदार्थ पिलायें। लगातार ठंडे पानी की पट्टियाँ रखें और नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सीय परामर्श लें।

पी.जी.डी.सी.ए. मात्र 9100/-
डी.सी.ए. मात्र 8100/-
न्यूनतम योग्यता पी.जी.डी.सी.ए.
स्नातक एवं डी.सी.ए.-बारहवीं (10+2)
मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ द्वारा संचालित
सहकारी कम्प्यूटर एवं प्रबंध
प्रशिक्षण केन्द्र, भोपाल
(माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से सम्बद्ध)
ई-8/77 शाहपुरा, त्रिलंगा, भोपाल (म.प्र.) पिनकोड-462 039
फोन.-0755 2725518, 2726160 फेक्स-0755 2726160
Email: rajyasanghbpl@yahoo.co.in,ccmtcbpl@rediffmail.com

श्रमिकों और पिछड़ों के कल्याण के बिना देश प्रगति नहीं कर सकेगा : राष्ट्रपति

10 हजार तेंदूपत्ता संग्राहकों को बोनस के रूप में दी गयी एक करोड़ की राशि

भोपाल। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने कहा कि यह एक सच्चाई है कि गरीबों, श्रमिकों और पिछड़ों के कल्याण के बिना कोई भी देश प्रगति नहीं कर सकता है, उनके कार्य में भी कौशल की जरूरत होती है। इसी प्रकार से तेंदूपत्ता संग्रहण करने का काम भी कुशलता का काम है। तेंदूपत्ता संग्रहक और उनके परिवार इस कार्य को अपने पारंपरिक ज्ञान से ही अच्छी तरह पूरा कर पाते है। इस कार्य से उनकी आजीविका चलने के साथ वनों का विनाश भी रुका है। राष्ट्रपति श्री कोविंद गुना जिले के सुदूर अंचल बमोरी में असंगठित मजदूर एवं तेंदूपत्ता संग्राहक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।

राष्ट्रपति श्री कोविंद ने ग्राम बमोरी में 127 करोड़ रुपये की लागत के विकास एवं निर्माण कार्यों का भूमि-पूजन एवं लोकार्पण किया। राष्ट्रपति ने 10 हजार तेंदूपत्ता संग्राहकों को बोनस के रूप में एक करोड़ रुपये की राशि प्रदाय की। राष्ट्रपति ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि वनों का संरक्षण और वनों से प्राप्त होने वाली उपज का सदुपयोग करके ही हम आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित रख सकते हैं। वनों को आदिवासी एवं वनवासी से बेहतर कोई नहीं जान सकता है, जंगल ही उनका रक्षक और पालक है। वे दोनों एक-दूसरे की रक्षा करते है, ऐसे में तेदूपत्ता संग्राहकों के कल्याण की जिम्मेदारी समाज और राज्य सरकार की है।

बाँस से बनने वाले उत्पादों के लिए मिशन मोड योजना

राष्ट्रपति ने कहा कि यह खुशी की बात है कि मध्यप्रदेश में लघु वनोपज संघ द्वारा मुख्यमंत्री तेंदूपत्ता संग्राहक कल्याण सहायता योजना शुरू की गई है। संघ के माध्यम से संग्राहकों के बच्चों की शिक्षा के लिए एकलव्य छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति दी जा रही है। श्री कोविंद ने कहा कि वनोपज का उचित मूल्य प्राप्त हो, आजीविका के लिए वनों पर आश्रित लोगों के जीवन में सुधार हो, इसके लिए केन्द्र सरकार द्वारा 24 लघु वनोपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना लागू की गई है। योजना से वनवासी भाई-बहनों को वनोपज का उचित मूल्य प्राप्त होगा, वहीं बाँस और उससे बनने वाले उत्पादों के संबंध में भी भारत सरकार ने मिशन मोड योजना शुरू की है। लघु वनोपज संघ द्वारा भी लघु वनोपज पर आधारित प्र-संस्करण केन्द्र संचालित किए जा रहे है। राष्ट्रपति श्री कोविंद ने कहा कि भारत में श्रम क्षेत्र में असंगठित क्षेत्रों का हिस्सा 80 प्रतिशत से अधिक है, जिसमें मुख्य रूप से ज्यादातर श्रमिक कृषि एवं निर्माण क्षेत्रों से जुड़े हुए है। असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा की भारी जरूरत है। इनके बीमार होने, अपंग हो जाने पर या वृद्धावस्था में किसी प्रकार की परेशानी खड़ी न हो, इसके लिए केन्द्र सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा संहिता बनाई जा रही है। उन्होंने इस दिशा में मध्यप्रदेश सरकार की सराहना करते हुए कहा कि राज्य सरकार पहले से ही इस दिशा में कार्य कर रही है। प्रदेश में लघु एवं कुटीर उद्योगों पर राज्य सरकार ने विशेष ध्यान दिया है। इसी का परिणाम है कि पिछले दो वर्षों में प्रदेश में लघु उद्योग इकाईयों के माध्यम से लगभग 6 लाख लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश में श्रमिकों के कल्याण के लिए शुरू की गई योजनाओं से श्रमिकों के जीवन-स्तर में आए सुधार का उल्लेख भी किया।

मध्यप्रदेश एकमात्र राज्य जहाँ गरीब बच्चों की फीस राज्य सरकार भरेगी

राज्यपाल श्रीमती आनंदी बेन पटेल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश सरकार ने गरीबों के कल्याण एवं उत्थान के लिए ऐसी कई योजनाएँ संचालित की है, जिसका लाभ जरूरतमंदों तक पहुँच रहा है। उन्होंने सभी वर्गों के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं के लिए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और उनके मंत्रि-मण्डल को बधाई दी। उन्होंने इस अवसर पर ग्रामीणों से आग्रह करते हुए कहा कि गरीबी से मुक्त होने का एक ही मंत्र है, शिक्षा। इसके लिए वे अपने बच्चों को पढ़ने के लिये अवश्य भेजें।

मध्यप्रदेश सरकार गरीब, किसान, मजदूर को केन्द्र में रखकर कार्य कर रही है

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि गुना जिले के सुदूर अंचल में पहली बार देश के राष्ट्रपति श्री कोविंद ने आकर इतिहास रचा है। साथ ही देश की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद भी साथ है। उन्होंने कहा कि आज का दिन गुना जिले के लिए एक अदभुत दिवस है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश में सभी वर्गों के साथ किसानों एवं मजदूरों के लिए भी काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी और पं. दीनदयाल उपाध्याय की सोच थी, कि जो व्यक्ति समाज की अंतिम पंक्ति पर खड़ा है उसका कल्याण सबसे पहले हो। इसी दिशा में राज्य सरकार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में रहने वाले प्रत्येक गरीब आवासहीन परिवार को भूखण्ड दिया जाएगा। इसके लिए प्रदेश में कानून बनाया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना एवं मुख्यमंत्री आवास योजना में आने वाले 4 वर्षों के अंदर सभी आवासहीन परिवारों को पक्के आवास दिए जायेंगे।

सौभाग्य योजना से 14 लाख 81 हजार से अधिक घरों में पहुंची बिजली

प्रदेश के 10 जिलों के सभी घरों में हुए बिजली कनेक्शन

भोपाल। मध्यप्रदेश में सौभाग्य योजना में अब तक 14 लाख 10 हजार 708 घरों में बिजली कनेक्शन कर दिये गये हैं। प्रदेश में कुल 28 लाख 80 हजार बिजली कनेक्शन विहीन घरों को अक्टूबर 2018 तक विद्युतीकृत करने का लक्ष्य है। इस योजना में अब तक 10 जिलों आगर-मालवा, मंदसौर, इंदौर, खण्डवा, नीमच देवास, रतलाम, हरदा, अशोकनगर और उज्जैन में विद्युतीकरण का लक्ष्य शत-प्रतिशत पूरा कर सभी घर बिजली से रौशन कर दिए गए हैं।

मध्यप्रदेश में केन्द्र सरकार के सहयोग से राज्य सरकार द्वारा बिजली विहीन सभी गरीब परिवारों के घरों में बिजली कनेक्शन किये जा रहे हैं। प्रदेश के तीन जिले सीहोर (99%), शाजापुर (99%) और भोपाल (96%) भी शीघ्र ही सौ फीसदी विद्युतीकरण की सूची में शामिल हो जायेंगे।

अब तक पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने 20 जिलों के 15 लाख 7 हजार 20 घरों में बिजली कनेक्शन देने के लक्ष्य के विरुद्ध 4 लाख 69 हजार 153 घरों में बिजली कनेक्शन कर दिये गये हैं। मध्य क्षेत्र कंपनी ने 16 जिलों के 18 लाख 55 हजार 325 घरों के विद्युतीकरण के लक्ष्य के विरुद्ध 6 लाख 3 हजार 555 घरों में बिजली कनेक्शन देकर उन्हें रौशन किया है। पश्चिम क्षेत्र कंपनी द्वारा अक्टूबर तक क्षेत्र के 15 जिलों में 7 लाख 16 हजार 851 गरीब परिवारों के घरों में बिजली कनेक्शन देने के लक्ष्य के विरुद्ध 3 लाख 38 हजार घरों में बिजली कनेक्शन कर दिए गए हैं।

सौभाग्य योजना में निर्धन परिवारों के घरों को मुफ्त बिजली कनेक्शन देने के लिये प्रदेश को 60 प्रतिशत राशि केन्द्र से अनुदान के रूप में मिलती है। शेष 40 प्रतिशत राशि का प्रबंध राज्य शासन एवं तीनों विद्युत कंपनी द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। इस योजना में आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को नि:शुल्क बिजली कनेक्शन दिए जा रहे हैं। अन्य लोगों से 500 रुपए की राशि 10 किश्तों में मासिक विद्युत बिल के साथ ली जाती है।

ग्राम सभाओं में 13 जून को श्रमिकों को हितलाभ वितरित होंगे

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल जिले की बैरसिया तहसील के ग्राम गुनगा में हुई विशेष ग्रामसभा में कहा कि 13 जून को ग्रामसभाएँ आयोजित कर असंगठित श्रमिक कल्याण योजना के पात्र हितग्राहियों को हितलाभ वितरित किये जायेंगे। इसके बाद यह काम लगातार जारी रहेगा।

श्री चौहान ने कहा कि महिला स्व-सहायता समूहों को सशक्त बनाने के लिये समूहों के ऋण का 3 प्रतिशत ब्याज राज्य सरकार भरेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि 10 जून को इस वर्ष गेहूँ विक्रय करने वाले किसानों को 265 रूपये प्रति क्विंटल की दर से प्रोत्साहन राशि दी जायेगी। उन्होंने कहा कि चना, मसूर और सरसों के समर्थन मूल्य पर भी 100 रूपये प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि श्रमिकों के कल्याण के लिये राज्य सरकार द्वारा असंगठित श्रमिक कल्याण योजना बनाई गई है। इस योजना से श्रमिकों के परिवार के सदस्यों को शासन की विभिन्न योजनाओं के सभी लाभ दिये जायेंगे। श्रमिकों को रहने के लिये जमीन का पट्टा दिया जायेगा और अगले चार साल में सभी को पक्के मकान बनवाकर दिये जायेंगे।

मध्यप्रदेश की सभी अवैध कालोनियों को वैध किया जायेगा : मुख्यमंत्री श्री चौहान

पात्र हितग्राहियों को 80 करोड़ के हित-लाभ वितरित : श्रमिकों को दिये पंजीयन कार्ड

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर में आयोजित भव्य समारोह में घोषणा की कि प्रदेश की सभी अवैध कॉलोनियों को वैध किया जायेगा। इस अभियान में प्रदेश की चिन्हित 6000 अवैध कॉलोनियों में से प्रथम चरण में 4624 कॉलोनियों को वैध किया जायेगा, जिनमें ग्वालियर शहर की 63 और डबरा शहर की 58 कॉलोनियाँ शामिल हैं।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अवैध कॉलोनियों को वैध किये जाने के नियमों का सरलीकरण किया जायेगा, ताकि सभी कॉलोनियाँ वैध हो सकें। उन्होंने कहा कि वैधानिक कार्यवाही के बाद इन कॉलोनियों के लोगों को सम्पत्ति बेचने और खरीदने के अधिकार होंगे और मकान में अतिरिक्त निर्माण के लिये बैंकों से कर्ज मिल सकेगा।

श्री चौहान ने इस अवसर पर विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को 80 करोड़ रुपये के हित-लाभ प्रदान किये। मुख्यमंत्री ने चरण-पादुका योजना में तेंदूपत्ता संग्राहक महिलाओं एवं पुरुषों को चरण-पादुकाएँ पहनाईं।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने समारोह में उपस्थित श्रमिकों, तेंदूपत्ता संग्राहकों और विशाल जन-समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि गरीब एवं श्रमिक परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिये राज्य सरकार ने क्रांतिकारी योजनाएँ शुरू की हैं। श्रमिकों के बच्चों को पब्लिक स्कूल की तरह गुणवत्तायुक्त शिक्षा मुहैया करवाने के लिये श्रमोदय विद्यालय खोले जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि ग्वालियर में 43 करोड़ रुपये लागत का श्रमोदय विद्यालय बनकर तैयार हो गया है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर राज्य सरकार की जन-कल्याणकारी योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी।

श्री चौहान ने इस मौके पर ग्वालियर के हजीरा अस्पताल को 100 बिस्तरीय अस्पताल में परिवर्तित करने की घोषणा की। साथ ही, ग्वालियर उप-नगर क्षेत्र की सड़कों के निर्माण के लिये समुचित धनराशि मुहैया करवाने का आश्वासन दिया। श्री चौहान ने समारोह के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये रतलाम, इंदौर, जबलपुर एवं भोपाल के महापौर से उनके क्षेत्रों में विकास कार्यों के बारे में चर्चा की।

केन्द्रीय पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने समारोह की अध्यक्षता करते हुए बताया कि केन्द्र एवं रा%य सरकार द्वारा प्रदेश के हर जरूरतमंद को पक्का घर मुहैया करवाया जायेगा। समारोह को नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्रीमती माया सिंह और महापौर श्री विवेक नारायण शेजवलकर ने भी संबोधित किया।

समारोह में उ%च शिक्षा मंत्री श्री जयभान सिंह पवैया, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाह, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री रुस्तम सिंह, सांसद श्री प्रभात झा, विधायक श्री भारत सिंह कुशवाह, सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष श्री बालेन्दु शुक्ल, ग्वालियर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री अभय चौधरी, साडा अध्यक्ष श्री राकेश जादौन और अन्य जन-प्रतिनिधि भी मौजूद थे।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के प्रयास किये जाएंगे

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पिछड़ा वर्ग के लिये राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार से राष्ट्रीय आयोग गठित करने और उसे संवैधानिक दर्जा दिलाने का अनुरोध किया जायेगा। पिछड़ा वर्ग के युवाओं में प्रतिभा, क्षमता और योग्यता की कोई कमी नहीं है, इन्हें शिक्षा एवं रोजगार के क्षेत्र में सभी सुविधाएँ मुहैया करवाई जायेंगी। मुख्यमंत्री ने सागर के समीप ग्राम बामौरा में पिछड़ा वर्ग महाकुंभ को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने पिछड़ा वर्ग की 15 विभूतियों को म.प्र. रामजी महाजन पिछड़ा वर्ग सेवा राज्य पुरस्कार-2015 प्रदान किये। साथ ही वर्ष 2017-18 म.प्र. लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न सेवाओं के लिये चयनित पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को सम्मानित किया। श्री चौहान ने शासन की विभिन्न योजनाओं के पात्र हितग्राहियों को हितलाभ भी वितरित किये।

अन्य पिछड़ा वर्ग को 5973 करोड़ की आर्थिक सहायता/अनुदान

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि राज्य सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग के विकास के लिये 5973 करोड़ रूपये की राशि आर्थिक सहायता और अनुदान के रूप में खर्च की है। राज्य सरकार की यह कोशिश निरंतर जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग स्व-रोजगार योजना में पिछले वित्त वर्ष में 111 करोड़ रूपये खर्च कर युवाओं को स्व-रोजगार से लगाया गया है। श्री चौहान ने प्रधानमंत्री फसल बीमा, मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि, समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदी, स्व-रोजगार योजनाओं और मुख्यमंत्री असंगठित श्रमिक कल्याण योजना की जानकारी देते हुए अपील की कि अपनी ग्राम पंचायत में आयोजित विशेष ग्राम सभाओं में जरूर शामिल हों। उन्होंने श्रमिक बंधुओं से आग्रह किया कि विशेष ग्राम सभाओं में जाकर अपने पंजीयन का सत्यापन करायें और मुख्यमंत्री असंगठित श्रमिक कल्याण योजना का भरपूर लाभ उठायें।

मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित विभूतियाँ

मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा महाकुंभ में म.प्र. रामजी महाजन पिछड़ा वर्ग सेवा राज्य पुरस्कार-2015 से श्रीमती कान्ति पटेल, श्रीमती आशा साहू, श्रीमती माया विश्वकर्मा, श्रीमती अलका सैनी, श्रीमती बबीता परमार, श्रीमती यमुना कछावा, श्रीमती प्रीति सेन, सुश्री राजकुमारी कुसुम महदेले (जबलपुर), श्री सूरज सिंह मारण, डॉ जे.के. यादव, श्री राजेश दोडके, डॉ. भगवान भाई पाटीदार, श्री काशीराम यादव और श्री महेन्द्र कटियार को सम्मानित किया। इन विभूतियों को पुरस्कार स्वरूप एक-एक लाख रूपये, स्मृति चिन्ह, प्रशस्ति-पत्र, शॉल-श्रीफल भेंटकर सम्मानित किया गया। स्व. श्री नारायण सिंह डागोर का मरणोपरांत पुरस्कार उनकी धर्मपत्नी श्रीमती चन्द्रादेवी ने प्राप्त किया। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती ललिता यादव ने समारोह की अध्यक्षता की। सांसद श्री लक्ष्मीनारायण यादव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव, गृह एवं परिवहन मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह, महापौर श्री अभय दर्रे, बुन्देलखंड विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष डा. रामकृष्ण कुसमरिया, विधायक श्री शैलेन्द्र जैन, श्रीमती पारूल साहू, श्री हरवंश राठौर, श्री प्रदीप लारिया, श्री महेश राय, श्री हर्ष यादव, म.प्र. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष श्री राधेलाल बघेल, पिछड़ा वर्ग तथा वित्त विकास निगम के अध्यक्ष श्री प्रदीप पटेल एवं अन्य स्थानीय जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे।

मध्यप्रदेश के आर्गनिक कॉटन की बेहतर मार्केटिंग व्यवस्था जरूरी

जैविक कपास सम्मेलन में किसान-कल्याण मंत्री श्री बिसेन

भोपाल। किसान-कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन ने कहा है कि मध्यप्रदेश आर्गनिक कॉटन के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में गिना जाता है। दुनिया के आर्गनिक कॉटन के कुल उत्पादन का 25 प्रतिशत उत्पादन मध्यप्रदेश में होता है। इसलिये प्रदेश में पैदा होने वाले आर्गनिक कॉटन की राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय-स्तर पर बेहतर मार्केटिंग की आवश्यकता है। श्री बिसेन आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी में जैविक कपास सम्मेलन में यह बात कही।

किसान-कल्याण मंत्री श्री बिसेन ने कहा कि मेडिकल के क्षेत्र में आर्गनिक कॉटन की माँग बढ़ी है। प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र की उत्कृष्ट कपास उत्पादन के लिये देशभर में विशिष्ट पहचान है। पिछले तीन-चार वर्षों में निमाड़ क्षेत्र में आर्गनिक कॉटन उत्पादन में किसानों ने रुचि दिखाई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिये वर्ष 2011 में जैविक नीति तैयार की है। इसमें किसानों को अनुदान के साथ-साथ अनेक सुविधाएँ दी जा रही हैं। किसानों की आय दोगुनी करने के उपायों की चर्चा करते हुए श्री बिसेन ने कृषि क्षेत्र में कार्यरत स्वयंसेवी संगठनों से राज्य सरकार के साथ मिलकर कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन करने का आग्रह किया।

प्रमुख सचिव किसान-कल्याण तथा कृषि विकास विभाग श्री राजेश राजौरा ने सम्मेलन में बताया कि प्रदेश में पहले वीटी कॉटन आया, लेकिन यह किसानों की लागत को कम करने में ज्यादा कारगर साबित नहीं हुआ। आर्गनिक कॉटन की चुनौतियों की चर्चा करते हुए श्री राजौरा ने कहा कि खरगोन, बड़वानी, झाबुआ और निमाड़ के कुछ

जिलों में उत्कृष्ट स्तर का आर्गनिक कॉटन उत्पादित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश का जैविक खेती का क्षेत्रफल पिछले 7 वर्षों में 7 गुना बढ़कर करीब 6 लाख हेक्टेयर हो गया है। प्रमुख सचिव ने बताया कि आर्गनिक कॉटन की बदौलत जैविक उत्पाद निर्यात को 600 करोड़ से बढ़ाकर 1000 करोड़ रुपये तक पहुँचाया जा सकता है। प्रमुख सचिव ने बताया कि मण्डला में जैविक कृषि संस्थान, जबलपुर में जैविक उत्पाद टेस्टिंग सेंटर और खण्डवा में आर्गनिक कॉटन शोध संस्थान शुरू किये जा रहे हैं।

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक दिनेशचंद्र शर्मा द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई-8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : दिनेशचंद्र शर्मा
डाक पंजीयन क्रमांक - म.प्र./भोपाल/357/2015-17 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2725518, फैक्स : 0755-2726160 इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।